Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 12, Issue 2 | November 2024 - April 2025 | pp. 86-93

भारतीय विदेश नीति की उभरती नवीन प्रवृत्तियाँ

दीपमाला जांगिड़

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

पिछले एक दशक में वैश्विक राजनीति में आए परिवर्तनों की प्रकृति विशेष रही है एवं इसका दायरा भी व्यापक रहा है। ऐसे में विदेश नीति में भी बुनियादी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। इन परिस्थितियों में, वैश्विक परिदृश्य के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए भारतीय विदेश नीति में भी कई नवीन प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है जो इसे अधिक लचीला, संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण से संपन्न बनाती हैं। ये प्रवृत्तियां 'भारत प्रथम' के सिद्धांत से प्रेरित हैं, जो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के साथ-साथ वैश्विक भागीदारी और बहुपक्षीय संस्थानों में उसकी स्थिति को मजबूत कर रही हैं। इसके साथ ही, 'पड़ोस प्राथमिकता' की नीति, 'एक्ट ईस्ट' नीति, 'सागर' पहल और 'लुक वेस्ट' नीति के माध्यम से एशियाई गोलार्ध और हिंद महासागर में भारत के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने में भी सहयोग प्रदान कर रही हैं। भारतीय विदेश नीति अपने 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक कूटनीति के माध्यम से अपने आर्थिक संबंधों के क्षेत्र का विस्तार कर रही है एवं महाशक्तियों के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए, रूस और अमेरिका दोनों के साथ अपनी साझेदारी को विस्तृत करने का कार्य कर रही है। यह बहुपक्षीय जुड़ाव और सॉफ्ट पावर कूटनीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भी अग्रसर कर रही है। इस संदर्भ को दृष्टिगत रखते हुए इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य भारतीय विदेश नीति की इन उभरती हुई प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना है, जो भारत को वैश्विक मंच पर प्रासंगिक बना रही हैं और उसके हितों की पूर्ति और संवर्धन के उद्देश्य को पोषित कर रही हैं।

संकेताक्षर—*विदेश नीति, राष्ट्रीय हित, व्यावहारिकता, आर्थिक सशक्तीकरण, पड़ोस प्राथमिकता, सक्रिय भागीदारी*

प्रस्तावना

विदेश नीति से तात्पर्य किसी देश की उस नीति से है जो अपने राष्ट्रीय हितों के संवर्धन हेतु अन्य देशों के साथ संबंधों के संचालन के लिए बनाई जाती है। यह उस देश के पारंपरिक मूल्य, आकांक्षाओं, सामूहिक चेतना एवं राष्ट्रीय नीतियों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब होती है। विदेश नीति की व्यापकता को स्पष्ट करते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपनी पुस्तक 'विश्वबंधु भारत' में विदेश नीति को वर्णित किया है। इसके प्रमुख अंश इस प्रकार है—"एक 'अच्छी' विदेश नीति को व्यक्तिगत रूप से आपके लिए काम करना चाहिए। बाहरी दुनिया से जुड़ी होने के नाते विदेश नीति हमें वह सब हासिल करने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए जो हम चाहते हैं। यह प्रौद्योगिकी, पूंजी, सर्वोत्तम प्रथाएँ या कार्य अवसर हो सकते हैं। अच्छी विदेश नीति को वैश्विक रुझानों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। शुभ का पूर्वानुमान लगाना चाहिए। अप्रत्याशित के प्रति त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया देनी चाहिए एवं हमारी छवि को सकारात्मक रूप से भी प्रस्तुत करनी चाहिए।"[1]

उन्होंने विदेश नीति के लचीलेपन एवं गतिशीलता पर विशेष रूप से बल दिया है। विदेश नीति का गतिशील होना एवं व्यावहारिक रूप से विकसित होना अनिवार्य होता है। उसकी

गतिशीलता उसे वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलित होने के लिए प्रेरित करती है एवं व्यावहारिकता उसे राष्ट्रीय हितों के पोषण की ओर निरंतर अग्रसर करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय विदेश नीति सदैव गत्यात्मक प्रकृति की रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर वर्तमान तक भारतीय विदेश नीति ने स्वयं को वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप समायोजित करने का प्रयास किया है। अतः उन सभी नवीन प्रवृत्तियों को भारतीय विदेश नीति में स्थान दिया गया है जो भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए आवश्यक हैं। भारत की विदेश नीति आर्थिक विकास, क्षेत्रीय स्थिरता, बहुपक्षीयता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में केंद्रित है। यह सीमा पार नवीन मुद्दा आधारित संबंधों को बनाने, पारंपरिक संबंधों को दृढ़ करने एवं अपनी वैश्विक छवि को सुधारने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। पिछले एक दशक में वह विचारधारा के अपेक्षाकृत अपनी आवश्यकताओं को जुड़ाव का एक प्रमुख आधार बना रही है।[2] अपने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं के सशक्तीकरण के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने एवं वैश्विक जिम्मेदारियों के प्रति एक विश्वसनीय और जिम्मेदार हितधारक की भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। 21वीं सदी का भारत एक स्थिर एवं समावेशी वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है। ऐसी वैश्विक व्यवस्था में स्वयं को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की अपनी महत्वाकांक्षा हेतु वह अपनी घरेलू एवं विदेश नीति को अधिक सक्रिय बनाने के हर संभव तरीके को अपनाने के लिए प्रयासरत है। विश्व में भारत को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपनी पुस्तक 'द इंडिया वे' में एक रणनीति बताई है जिसके अनुसार "यह एक ऐसा समय है जब हमें अमेरिका से जुड़ना चाहिए, चीन को प्रबंधित करना चाहिए, यूरोप से संबंध बनाने चाहिए, रूस को आश्वस्त करना चाहिए, पड़ोसियों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना चाहिए, पड़ोस का विस्तार करना चाहिए एवं पारंपरिक भरोसे वाले क्षेत्र का दायरा बढ़ाना चाहिए"।[3] भारतीय विदेश नीति ने इस संदर्भ में कई स्तरों पर सुचारु रूप से प्रगति की है लेकिन अभी भी कई मुद्दों पर समान रूप से प्रगति नहीं हुई है। उनकी प्राप्ति में वैश्विक व्यवस्था की चुनौतियाँ प्रमुख रूप से उत्तरदायी रही है जैसे कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति, दक्षिण एशियाई देशों में राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट, चीन एवं पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद प्रमुख हैं।

वर्तमान भारत विश्व-बंधु भारत बनने के लिए विकास की एक अनवरत यात्रा पर चल पड़ा है। इसके लिए वह न केवल वैदेशिक स्तर पर अपितु घरेलू स्तर पर भी उन सभी नीतियों का पालन कर रहा है जो उसके राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देती है और वैश्विक स्तर पर उसकी प्रासंगिकता का निरंतर दावा भी करती हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने लेख 'विश्वबंधु' में भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त किया है। इसके कुछ प्रमुख अंश इस प्रकार हैं— "आदर्श रूप से देश दुनिया का सर्वोत्तम लाभ उठाने के लिए अपनी विदेश नीति बनाते हैं जिसका लक्ष्य संसाधनों, बाजार, प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं तक पहुंच को विकसित करना होता है। भारतीय मामले में यह ध्यान 2014 से तीव्र रहा है। अब बड़ा बदलाव भारत प्रथम की भावना है। जहां प्राथमिक रूप से राष्ट्रीय हित का उपयोग करने का विश्वास है। एक ऐसी कूटनीति को अपनाना है जो साझेदारों को अधिकतम करेगी एवं समस्याओं को कम करेगी। जहां हमें अपना पक्ष रखना है वहां हम दबाव रहित है। साथ ही हमारी प्रासंगिकता का भी निरंतर दावा होता रहता है। यह निर्विवाद रूप से विश्वबंधु भारत है।"[4]

भारत ने अपने विकास की दीर्घ यात्रा को तय करने के लिए अपनी विदेश नीति में जिन नवीन प्रवृत्तियों का समावेश किया है उन्हें निम्न शीर्षकों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

व्यावहारिकता की ओर अधिक झुकाव की नीति

21वीं सदी के आरंभ में भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोण में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है इसका व्यावहारिकता की ओर अधिक झुकाव। अतीत की तुलना में, भारतीय विदेश नीति ने व्यापक रूप से व्यावहारिकता का प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 'भारत प्रथम' के सिद्धांत को सर्वोपरि मान्यता प्रदान कर रही है। 'भारत प्रथम' का तात्पर्य अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और जहां भारतीय हित हैं, वहां साझेदारी विकसित करने से है। भारत अपने अतीत के वैचारिक दृष्टिकोण को त्यागकर विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी साझेदारी और सहयोग को बढ़ाने और विकसित करने का प्रयास कर रहा है।

अपने एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण की वकालत करते हुए कहा कि "दुनिया आपस में जुड़ी हुई है एवं एक दूसरे पर निर्भर भी है। विदेशी मामलों में हमारा सबसे प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत

राष्ट्रीय हित है। यह रुख हमें विभिन्न देशों के साथ इस तरह से जुड़ने की अनुमति देता है जो आपसी हितों का सम्मान करता है और समकालीन भू-राजनीति की जटिलताओं को स्वीकार करता है।" [5]

प्रधानमंत्री मोदी का यह कथन भारतीय विदेश नीति के व्यावहारिकता को परिभाषित करता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि विदेश नीति सदैव राष्ट्रीय हितों से प्रेरित रही है एवं भविष्य में वैदेशिक संबंधों के संचालन के संदर्भ में रहेगी। यहां पर मुख्य सन्दर्भ इस तथ्य को रेखांकित करना है कि भारतीय विदेश नीति पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में व्यावहारिकता के पैमाने पर अधिक खरी उतरती है। यह अपने आदर्शों की अपेक्षा अपने हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है एवं अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने आदर्शों एवं हितों के मध्य उचित संतुलन बनाती प्रतीत हो रही है। इसकी अधिक सक्रियता एवं विस्तृत सहभागिता के पीछे मुख्य मंशा अपने हितों की अधिकाधिक पूर्ति है। भारत अब अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों को सर्वोच्च वरीयता देते हुए वैश्विक राजनीति में एक स्वतंत्र रुख अपनाने की दिशा में अग्रसर है और किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव से प्रभावित होने से इंकार करता है। यूक्रेन संघर्ष और क्वाड में अपनी सदस्यता के संदर्भ में भारत ने संतुलित और व्यावहारिक विदेश नीति का स्पष्ट संकेत दिया है। रूस पर आक्रमणों के कारण लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद, भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रखा है। यह निर्णय भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है।

भारत की पड़ोस नीति का बदलता स्वरूप

समग्र विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत एक सुरक्षित, स्थिर और सहयोगी पड़ोस के महत्व को स्वीकार करता है। भारत के बढ़ते आर्थिक और सामरिक हित इसे दक्षिण एशियाई देशों से आगे एशियाई गोलार्ध के साथ तेजी से जोड़ रहे हैं। पड़ोस के संदर्भ में भारत की विदेश नीति सर्वदिशात्मक होती जा रही है। भारत अब पूर्व की ओर ही नहीं, बल्कि उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम की ओर भी देख रहा है, जो इसके विस्तारित पड़ोस और इसके आगे के दायरे में सम्मिलित है। भारत अपनी इस नीति के तहत अपने सभी पड़ोसियों के साथ महत्वपूर्ण संबंध विकसित करने, अंतर्निर्भरता को बढ़ावा देने और एक-दूसरे की संप्रभुता में सहयोग करने का प्रयास कर रहा है। भारत की पड़ोस नीति के अंतर्गत निकट पड़ोस के साथ विस्तारित पड़ोस की अवधारणा भी शामिल है। भारत के निकट पड़ोस में दक्षिण एशिया के सभी देश सम्मिलित हैं और विस्तारित पड़ोस पश्चिम एशिया से दक्षिण चीन सागर तक फैला है। इसके तहत पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, प्रशांत और हिंद महासागर आते हैं।

भारत ने अपनी निकटतम पड़ोस और विस्तारित पड़ोस को अपनी नीतिगत पहल के माध्यम से मान्यता प्रदान की है। भारत ने अपनी निकटवर्ती पड़ोस के साथ संबंधों के सुचारु संचालन हेतु 'पड़ोस प्राथमिकता' की नीति, दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ 'एक्ट ईस्ट नीति', समुद्री सीमा वाले पड़ोसी देशों के साथ 'सागर पहल', और पश्चिमी देशों के साथ 'लुक वेस्ट' नीति का प्रतिपादन किया है।

पड़ोस प्राथमिकता की नीति

मोदी सरकार ने 'पड़ोस प्राथमिकता' की नीति के तहत पड़ोसी देशों के महत्व को मान्यता प्रदान की है। इस नीति का प्रारंभिक संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सभी दक्षिण एशियाई देशों के प्रमुखों को निमंत्रण दे कर दिया। अपनी प्रथम विदेश यात्रा गंतव्य के रूप में भूटान का चुनाव भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इसे भारत की बहुत स्पष्ट प्राथमिकता मानती है और इसे मोदी की फास्ट ट्रेक कूटनीति का हिस्सा बताती है।[6]

भारत अपनी इस नीति के तहत अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने, अंतर निर्भरता को बढ़ावा देने, जुड़ाव को विकसित करने एवं एक दूसरे की स्थिरता में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत इस क्षेत्र का सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला सशक्त देश है अतः वह इस क्षेत्र में अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारी से पूर्ण रूप से अवगत है। भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों को आर्थिक एवं मानवीय सहायता प्रदान करके उनके विकास में योगदान दे रहा है। भारत भूटान की नियोजित विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उसके पंचवर्षीय योजना को वित्तीय सहायता दे रहा है। भारत ने मालदीव की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। बांग्लादेश को भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत 7.862 अरब अमेरिकी डॉलर के चार लाइन ऑफ़ क्रेडिट प्रदान किए हैं। नेपाल को इसकी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए 1.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता दे रहा है। श्रीलंका के लिए भारत की समग्र प्रतिबद्धता 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।[7]

तालिका : विदेशी सरकारों को अनुदान और ऋण

(करोड़ों में)

मंत्रालय/विभाग	वास्तविक आंकड़े 2023-2024			बजट अनुमान 2024-2025			संशोधित अनुमान 2024-2025			बजट अनुमान 2025-2026		
	अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल
1. विदेश मंत्रालय	**5008.30**	**1611.99**	**6620.29**	**4677.86**	**989.70**	**5667.56**	**6212.31**	**869.70**	**7082.01**	**6375.00**	**375.00**	**6750.00**
1. सांस्कृतिक एवं विरासत परियोजना के लिए सहायता	7.98	-	7.98	15.00	-	15.00	15.00	-	15.00	20.00	-	20.00
2. अफगानिस्तान	207.26	-	207.26	200.00	-	200.00	50.00	-	50.00	100.00	-	100.00
3. बांग्लादेश	157.63	-	157.63	120.00	-	120.00	120.00	-	120.00	120.00	-	120.00
4. भूटान	720.03	1611.99	2332.02	1078.86	989.70	2068.56	1673.78	869.70	2543.48	1775.00	375.00	2150.00
5. नेपाल	657.38	-	657.38	700.00	-	700.00	700.00	-	700.00	700.00	-	700.00
6. श्रीलंका	119.37	-	119.37	245.00	-	245.00	300.00	-	300.00	300.00	-	300.00
7. मालदीव	832.83	-	832.83	400.00	-	400.00	470.00	-	470.00	600.00	-	600.00
8. मंगोलिया	3.45	-	3.45	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00
9. अन्य विकासशील देश	112.85	-	112.85	125.00	-	125.00	125.00	-	125.00	150.00	-	150.00
10. आपदा राहत	41.18	-	41.18	10.00	-	10.00	60.00	-	60.00	64.00	-	64.00
11. अफ्रीकी देश	184.76	-	184.76	200.00	-	200.00	200.00	-	200.00	225.00	-	225.00
12. यूरेशियाई देश	28.75	-	28.75	20.00	-	20.00	30.00	-	30.00	40.00	-	40.00
13. लैटिन अमेरिकी देश	51.13	-	51.13	30.00	-	30.00	90.00	-	90.00	60.00	-	60.00
14. चाबहार बंदरगाह	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
15. मॉरीशस	358.87	-	358.87	370.00	-	370.00	576.00	-	576.00	500.00	-	500.00
16. सेशेल्स	6.18	-	6.18	40.00	-	40.00	37.00	-	37.00	19.00	-	19.00
17. म्यांमार	352.96	-	352.96	250.00	-	250.00	400.00	-	400.00	350.00	-	350.00
18. अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण/कार्यक्रमों को समर्थन	1131.89	-	1131.89	769.00	-	769.00	1260.53	-	1260.53	1247.00	-	1247.00
19. वास्तविक वसूली-	66.20	-	66.20	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. वित्त मंत्रालय	**2447.32**	**-**	**2447.32**	**3954.34**	**-**	**3954.34**	**3953.70**	**-**	**3953.70**	**136.79**	**-**	**136.79**
1. भारतीय विकास और आर्थिक विकास के अंतर्गत ऋण की लाइनें सहायता योजना (आईडीईएएस)	2350.00	-	2350.00	3849.00	-	3849.00	3849.00	-	3849.00	27.10	-	27.10
2. अन्य के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग देश (अंतर्राष्ट्रीय योगदान)	77.32	-	77.32	81.31	-	81.31	80.67	-	80.67	85.66	-	85.66
3. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	20.00	-	20.00	24.03	-	24.03	24.03	-	24.03	24.03	-	24.03
कुल योग	**7455.62**	**1611.99**	**9067.61**	**8632.20**	**989.70**	**9621.90**	**10166.01**	**869.70**	**11035.71**	**6511.79**	**375.00**	**6886.79**

स्रोत : एचटीटीपीएसः//डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इंडियाबजट डॉट जीओवी डॉट इन/डॉक/ईबी/स्टेट20 डॉट पीडीएफ

ISSN 2348-3857

अफगानिस्तान में भारत शुरुआत से ही विकास परियोजनाओं में निवेश को लेकर प्रतिबद्ध रहा है। तालिबान के अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ होने के उपरांत भी भारत अफगानिस्तान को हर संभव मानवीय सहायता पहुंचाने का कार्य कर रहा है। भारत का निकटतम पड़ोस स्वयं में एक जटिल रणनीतिक और विदेश नीतिगत चुनौती प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र में पड़ोसी देशों ने भारत को एक हस्तक्षेपकारी शक्ति के रूप में देखा है। भारत अपनी सकारात्मक पहलों के बावजूद नकारात्मक धारणाओं का पूरी तरह से मुकाबला करने में सफल नहीं हो पाया है।

एक्ट ईस्ट नीति

यह नीति लुक ईस्ट नीति के सिद्धांत पर आधारित है, जो राजनीतिक और रणनीतिक जुड़ाव के संदर्भ में अधिक उन्नत मार्ग प्रशस्त करती है। यह नीति गतिशील रणनीति पर जोर देती है। इसके तहत, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ न केवल आर्थिक स्तर पर बल्कि सुरक्षा, रणनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी जुड़ाव को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। इस नीति के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं—रणनीतिक साझेदारी, बहुपक्षीय जुड़ाव, समुद्री सुरक्षा, सांस्कृतिक संबंध, और बुनियादी ढांचे का विकास। यह नीति दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापक जुड़ाव और सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।

लुक वेस्ट नीति

पश्चिम एशिया भारत के विस्तारित पड़ोस में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है। यह क्षेत्र विशाल भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति, ऊर्जा आपूर्ति, सुरक्षा, व्यापार मार्ग और निवेश के प्रचुर स्रोतों के कारण भारतीय विदेश नीति में प्रमुख स्थान रखता है। भारतीय विदेश नीति की नवीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में, पश्चिम एशिया के साथ भारत के जुड़ाव को लुक वेस्ट नीति कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से खाड़ी देश, ईरान, इजरायल और अरब देशों के अधिक महत्वपूर्ण और समृद्ध क्षेत्र शामिल हैं। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देते हुए क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास में वृद्धि करना है। यह नीति ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। ऊर्जा सहयोग के साथ-साथ सुरक्षा सहयोग और सांस्कृतिक सहयोग भी इस नीति के प्रमुख पहलू हैं। भूमि संपर्क इस नीति की एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। इसलिए, भारत को वैकल्पिक मार्गों की संभावनाएं तलाशनी चाहिए और अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करने के लिए रूस, चीन और पश्चिम के बीच निरंतर संतुलन बनाए रखना चाहिए।

सागर पहल

भारत हिंद महासागरीय क्षेत्र में अपने समुद्री पड़ोसियों और द्वीप राज्यों के साथ परस्पर सहयोग को बढ़ाने, सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपनी भूमिका के प्रति सजग है। भारत की सागर पहल हिंद महासागर के लिए भारत के दृष्टिकोण की एक उच्च स्तरीय स्पष्ट अभिव्यक्ति है। भूमि और समुद्री क्षेत्र और हितों की सुरक्षा के लिए क्षमता बढ़ाना, तटीय क्षेत्र में आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना, प्राकृतिक आपदाओं और समुद्री जोखिमों से निपटने के लिए सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देना, बढ़े हुए सहयोग के माध्यम से सतत क्षेत्रीय विकास की दिशा में काम करना, समुद्री नियमों, मानकों और विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे हेतु सभी तटीय देशों के साथ जुड़ना इस पहल की प्राथमिकताएं हैं।

इस प्रकार भारत की पड़ोस प्राथमिकता नीति, एक्ट ईस्ट नीति, लुक वेस्ट नीति एवं सागर पहल भारतीय विदेश नीति के पड़ोस के संदर्भ में एक व्यापक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। यह दृष्टिकोण पूर्व की अपेक्षा अधिक सक्रिय एवं गतिशील प्रतीत होता है जो अपने हितों एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिए पड़ोस के साथ जुड़ाव को विशेष महत्व प्रदान करता है।

बहुपक्षीय जुड़ाव की नीति

बहुपक्षीय जुड़ाव की नीति से आशय है अपने साझे हितों एवं वैश्विक मुद्दों के प्रति संगठित होकर कार्य करना। इसके तहत विभिन्न देश एक मंच एवं संगठन के रूप में एकीकृत होकर सहयोग की भावना के तहत मिलकर कार्य करते है ।भारत अपनी बहुपक्षीय जुड़ाव की नीति के माध्यम से पश्चिमी देशों, रूस, चीन एवं अमेरिका के साथ संतुलन बनाए रखने का कार्य कर रहा है इसी के साथ वैश्विक दक्षिण को एकीकृत करने एवं उनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों का साझा समाधान निकालने में भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है भारत की यह नीति एक विवेकपूर्ण संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह

न केवल भारत की वैश्विक भूमिका को सशक्त करती है अपितु विकासशील दुनिया की आकांक्षाओं को भी स्वर देती है। भारत की जी-20, संयुक्त राष्ट्र संघ, आई.एम.एफ, विश्व बैंक, डब्ल्यू.टी.ओ. जैसे मंचों और जलवायु सम्मेलन जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में दक्षिण के देशों की हितों की वकालत करता है।

वर्तमान समय में भारत अपनी क्षेत्रीय सीमाओं से परे जाकर वैश्विक स्तर पर बहुपक्षीय जुड़ाव को प्रोत्साहित कर रहा है। इस बहुपक्षीय जुड़ाव का मुख्य उद्देश्य परिणामों और लाभों को बढ़ाना तथा वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना है।[8] भारत जी-20, बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग संवाद, शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, चतुष्कोण, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, लाइफ अभियान आदि में सक्रिय भागीदारी कर रहा है। भारत का बहुपक्षीय जुड़ाव उसकी वर्तमान विदेश नीति का केंद्रीय स्तंभ बना हुआ है। यह विदेश नीति केवल स्व हितों की पूर्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक दायित्व, सहयोग, और सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

महाशक्तियों के साथ संतुलित नीति

भारतीय विदेश नीति वर्तमान में महाशक्तियों के साथ संतुलन बनाए रखने के उच्चतम स्तर पर कार्यरत प्रतीत होती है। भारत अमेरिका और रूस दोनों के साथ संतुलित संबंध स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वर्तमान में भारत और अमेरिका के संबंध अभूतपूर्व सुधार के दौर में हैं। पारस्परिक लाभ के साथ-साथ दोनों देशों ने वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी साझेदारी विकसित की है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को इक्कीसवीं सदी में स्थाई वैश्विक साझेदार के रूप में परिभाषित किया है। अमेरिका ने वर्ष 2016 में भारत को मुख्य रक्षा साझेदार का दर्जा दिया है।[9] पिछले एक दशक में भारत अमेरिका रक्षा संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। यह भारत की रक्षा स्रोतों में विविधता लाने की नीति को दर्शाता है। भारत अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्वाड हिन्द महासागरीय क्षेत्र में चीन को प्रबंधित करने की एक संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य हिन्द महासागरीय क्षेत्र को खुला एवं स्वतंत्र क्षेत्र घोषित करना है। इसके अलावा भारत आर्थिक क्षेत्र में भी अमेरिका के साथ अपने सहयोग को बढ़ा रहा है। वर्ष 2021-2022 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार रहा है। मोदी सरकार के काल में भारत-अमेरिका संबंधों में एक अभूतपूर्व प्रगति देखी गयी है। यह इस दशक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी ज सकती है।

भारत ने रूस के साथ भी अपने पारंपरिक और करीबी रणनीतिक संबंधों को संरक्षित किया है एवं द्विपक्षीय स्तर पर रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, विज्ञान, और प्रौद्योगिकी में ऐतिहासिक सहयोग को आगे बढ़ाया है। यूक्रेन संकट के दौरान भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की है। अमेरिका के CAATSA प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से S-400 मिसाइल की खरीद जारी रखी है। भारत रूस के साथ अपनी पुरानी मित्रता को बनाए रखना चाहता है। भारत का अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाए रखना एक व्यावहारिक और संतुलित विदेश नीति का प्रतीक है। भारतीय विदेश नीति यह प्रमाणित करने का प्रयास कर रही है कि भारत बिना किसी दबाव के अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए दोनों देशों के साथ मित्रवत संबंध बनाए रख सकता है।

सॉफ्ट पावर कूटनीति

सॉफ्ट पावर किसी देश की विदेश नीति के उद्देश्य और प्राथमिकताओं को गैर दबाव पूर्ण तरीकों से आगे बढ़ाने की एक क्षमता है। पिछले एक दशक में भारत ने कूटनीति के अभ्यास में अपनी सॉफ्ट पावर को अधिक व्यवस्थित तरीके से प्रयोग में लिया है। भारतीय आध्यात्मिकता, संस्कृति, योग, नृत्य कला, व्यंजन कला, धार्मिक पर्यटन एवं भारतीय प्रवासी प्रमुख रूप से भारत की सॉफ्ट पावर के स्रोत है। सॉफ्ट पावर कूटनीति का प्रयोग भारत अपने अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने, वैदेशिक संबंधों को बेहतर बनाने एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कर रहा है। यह भारतीय विदेश नीति का एक सशक्त व्यावहारिक उपकरण है जो राष्ट्रीय हितों के संवर्धन के साथ-साथ वैश्विक छवि को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

वर्तमान में सॉफ्ट पावर कूटनीति भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन चुकी है। भारत अपनी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, और नैतिक शक्तियों के माध्यम से बिना किसी दबाव या युद्ध के अपने हितों की सुरक्षा कर रहा है। 2015 में योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की पहल, मोटे

अनाज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाना, चिकित्सा परंपराओं का तेजी से प्रसार, पर्यावरण और जीवन शैली के आपसी संबंधों को उजागर करना, प्रवासी भारतीयों से संपर्क साधना, और भारतीय सिनेमा एवं संगीत के माध्यम से भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को विश्व स्तर पर फैला रहा है।[10] भारत मानवीय सहायता और विकास सहायता के माध्यम से भी अपनी सॉफ्ट पावर कूटनीति को आगे बढ़ा रहा है। कोविड महामारी के दौरान साझेदारों को वैक्सीन और 150 से अधिक देशों को दवाइयां और अन्य सामग्री भेजकर भारत ने अपनी वैश्विक जिम्मेदारी का एक नया स्तर प्रदर्शित किया है। यह कार्यक्रम भारत की विदेश नीति में सॉफ्ट पावर कूटनीति को एक सांस्कृतिक और नैतिक उपकरण के रूप में स्थापित करता है जो न केवल भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर करता है बल्कि विश्व में भारतीय मूल्यों का भी प्रचार करता है।

आर्थिक कूटनीति

आर्थिक कूटनीति राज्यों के आपसी संबंध संचालन में आर्थिक हितों की रक्षा करने की एक कला है जिसका बुनियादी उद्देश्य व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना, बहुपक्षीय व्यापार वार्ता में उद्देश्यों को प्राप्त करना, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक कार्यवाही के माध्यम से राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। पिछले दशक में आर्थिक कूटनीति भारत की विदेश नीति का मुख्य केंद्र बिंदु रही है। भारत के नीति निर्माता इस तथ्य से पूर्ण रूप से परिचित रहे हैं कि यदि भारत को विकसित राष्ट्र का स्वप्न पूरा करना है तो उसे आर्थिक रूप से सशक्त बनाना अनिवार्य है। भारत की आर्थिक कूटनीति के प्रमुख पहलुओं में मुक्त व्यापार समझौते, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते, निवेश हेतु प्रोत्साहन कार्यक्रम इत्यादि शामिल है। इस हेतु घरेलू स्तर पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, आत्मनिर्भर भारत एवं स्किल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

आर्थिक कूटनीति का भारतीय मॉडल अब मुक्त व्यापार समझौता और आर्थिक गलियारों के निर्माण पर अपनी आर्थिक कूटनीति के महत्वपूर्ण चालकों के रूप में गंभीरता से विचार कर रहा है। भारत की आर्थिक कूटनीति अब नवीन तरीकों से संचालित हो रही है। वर्षों से यह आधिकारिक विकास सहायता के माध्यम से विकास साझेदारी पर निर्भर था लेकिन अब भारत एक उभरते हुए दाता के रूप में दिखाई देता है। इसने वैश्विक दक्षिण की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने विकास के अनुभव को साझा करने को प्राथमिकता दी है। उसने कई वर्षों से आर्थिक नीति को विकास साझेदारी के साथ जोड़ा है। आर्थिक विकास साझेदारी के रूप में भारत की आर्थिक कूटनीति मुख्य रूप से मांग संचालित है एवं मेजबान देश की प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित है। भारत की आर्थिक कूटनीति समय के साथ परिपक्व और अधिक सक्षम हो गई है। रूस यूक्रेन संकट, मध्य एशिया का गाजा संघर्ष, अमेरिका की संरक्षण वादी नीतियाँ इत्यादि में आर्थिक कूटनीति को विदेशी संबंधों के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक बना दिया है। ऐसे समय में भारत सहयोग के नवीन क्षेत्र की खोज कर रहा है जिनमें डिजिटल अर्थव्यवस्था, व्यापार सुविधा, सीमा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था, आर्थिक गलियारा इत्यादि शामिल है। इस दिशा में संतोषजनक प्रगति हुई है। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, और जापान के बाद भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय विदेश नीति ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख महाशक्तियों के साथ अपने व्यापार संबंधों को उच्च स्तर तक विकसित किया है, क्षेत्रीय शक्तियों तक अपनी पहुंच को बढ़ाया है, और विदेशी निवेश को आकर्षित करके घरेलू स्तर पर डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, और स्किल इंडिया कार्यक्रमों के माध्यम से विदेशी कंपनियों को निवेश और व्यापार हेतु प्रोत्साहित किया है। विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर कर भारत ने अपने आर्थिक संबंधों के क्षेत्र को विस्तृत किया है। दिसंबर 2020 में भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी आर्थिक कूटनीति वेबसाइट शुरू की है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापार की संभावना, भारत के साथ व्यापार करने में आसानी सूचकांक, क्रेडिट रेटिंग, और वैश्विक नवाचार सूचकांक आदि के बारे में जानकारी प्रदान करती है।[11]

आगे की राह

भारतीय विदेश नीति विकास की नवीन राह पर अग्रसर हो रही है। ऐसे में उसे उन सभी प्राथमिकताओं पर ध्यान देने की महती आवश्यकता है जो उसे अपने विकास की दिशा की ओर बढ़ने में सहायता प्रदान करती है इनमें सबसे प्रमुख प्राथमिकता

रणनीतिक संतुलन के साथ अपनी नीति निर्माण स्वायत्तता को बनाए रखना है। भारत को अपने आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए निवेश एवं व्यापार बढ़ाने हेतु अपनी नियमावली को सहज एवं पारदर्शी बनाना होगा। जिससे विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। भारत अपनी साझेदारी को अफ्रीकी, लेटिन अमेरिकी एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ विस्तृत करके अपने वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व की भूमिका को सुदृढ़ बना सकता है। भारत को दक्षिण एशिया में स्थिरता एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वहन करना होगा।

निष्कर्ष

भारत की विदेश नीति अब एक स्थिर सिद्धांत से अधिक जीवंत और गतिशील प्रक्रिया बन चुकी है जो वैश्विक अस्थिरता और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के युग में निरंतर विकसित हो रही है। हाल के वर्षों में भारत ने यह स्पष्ट किया है कि वह केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है बल्कि वैश्विक नीतिगत निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। भारत की विदेश नीति एक ऐसी दूरदर्शी यात्रा है जो राष्ट्रीय हित को वैश्विक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ती है। भारतीय विदेश नीति की नवीन प्रवृत्तियां विश्व में भारत के प्रभाव का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

सन्दर्भ सूची

1. जयशंकर, एस. (अनुवादित सुजाता शिवेन द्वारा) विश्वबंधु भारत, रूपा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2024, पृ.सं. 11-13
2. पंत, हर्ष वी., ए डिकेड ऑफ़ मोदीज फॉरेन पालिसी इंडिया शोज द वे, ओ.आर.ऍफ़ स्पेशल रिपोर्ट क्रमांक 228, 31 मई 2024, पृ.सं. 427 एक्सेस ऑन 22 जनवरी 2025
3. जयशंकर, एस. (अनुवादित दीपक नरेश द्वारा) द इंडिया वे, परिवर्तनशील विश्व में भारत की रणनीति, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2020, पृ.सं. 24
4. जयशंकर, एस., द विश्वबंधु भारत, हिंदुस्तान टाइम्स, 3 मई 2024
5. मिक्स-एन्ड-मैच फॉरेन पॉलिसी, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू .पीएमइंडिया.जीओवी.आईएन पर 21 दिसंबर, 2023 को प्रकाशित (30 अप्रेल, 2025 को प्राप्त किया)
6. महापात्रा, अनिल कुमार, मोदी सरकार की पड़ोस कूटनीति : प्रारम्भिक संकेत और पुरानी चुनौतियाँ, वर्ल्ड फोकस, मार्च 2015, पृ.सं. 91
7. लोक सभा प्रश्न संख्या 1342, बाइलेटरल रिलेशन्स विथ नेबरिंग कंट्रीज, 28 जुलाई 2022 को प्रकाशित (एक्सेस ऑन 13 जनवरी 2025)
8. खोब्रागडे, विनोद, भारत का समकालीन बहुपक्षवाद : ब्रिक्स और क्वाड का विश्लेषण, वर्ल्ड फोकस, दिसंबर 2021, पृ.सं. 36
9. जोशी, मनोज, अ सर्वे आफ इंडिया यूएस डिफेन्स कोऑपरेशन, ओ.आर.ऍफ़ स्पेशल रिपोर्ट क्रमांक 224, 15 मार्च 2024, पृ.सं. 12 (एक्सेस ऑन 3 मार्च 2025)
10. चौहान, भारती और पार्थ, भारत की सॉफ्ट पावर : ब्रिक्स में संस्कृति, प्रौद्योगिकी और नेतृत्व, वर्ल्ड फोकस, जून 2024, पृ.सं. 99
11. शुक्ला, सुभाष एवं मिश्रा, निखिल, मोदी सरकार के तहत भारत की आर्थिक कूटनीति 2014-2024, वर्ल्ड फोकस, जून 2024, पृ.सं. 55